>

Title: FDI in Retail sector.

श्रीमती नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): अध्यक्ष महोदया, मैं 21 जुलाई, 2010 को बिजनेस भास्कर में जो प्रैस रिपोर्ट आयी थी, उस बारे में बताना चाहता हूं। मल्टी ब्रांड रिटेल को लेकर यूपीए सरकार एक बार फिर से छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी पर धावा बोलने जा रही है।

महोदया, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश के साथ-साथ एक विकासशील देश भी है। हमारे देश में जनसंख्या का बड़ा बोझ होने के कारण एक लंबे अर्से से बेरोजगारी की समस्या चलती आ रही है। लोगों के पास इतनी पूंजी नहीं है कि वें बड़ा व्यापार कर सकें, इसलिए हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग मल्टी ब्रांड रिटेल के साथ सीधे जुड़ा हुआ है। हमारे देश की जीडीपी में रिटेल की हिस्सेदारी लगभग दस प्रतिशत है और प्रत्येक वर्ष आठ से नौ प्रतिशत की वृद्धि भी हो रही है। यदि आंकड़ों के अनुसार देखा जाये, तो पांच करोड़ से अधिक मध्यम वर्ग के व्यापारी, छोटे-छोटे वर्ग के व्यापारी रिटेल से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और 20 करोड़ से अधिक अन्य लोग ऐसे हैं जो अपनी रोजी-रोटी के लिए रिटेल व्यापार पर निर्भर करते हैं।

महोदया, यदि केन्द्र सरकार मल्टी ब्रांड रिटेलर, एफडीआई को इजाजत दे देती है, तो उसका फायदा वालमार्ट, केरियरफोर्ट, टेसको और मेट्रो जैसी दुनिया की बड़ी कम्पनियों को मिलेगा। इसके विपरीत हमारे देश के साढ़े तीन करोड़ से अधिक गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के व्यापार पर उसका सीधा असर पड़ेगा। आज इस खुदरा कारोबार में साढ़े तीन करोड़ देशवासी लगे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर असंगठित क्षेत्र के हैं और गांव, गली-मोहल्लों में छोटी-बड़ी दुकानें खोलकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। आज पूरे देश में महंगाई ने गरीब परिवार का जीना मुश्किल कर दिया है और इस सरकार की नीति को देखते हुए यह साफ जाहिर होता है कि सरकार की नीति गरीब जनता के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लिए है। यदि सरकार अपनी नीति नहीं बदलेगी तो सभी छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी धरना-प्रदर्शन करेंगे और अपने रोजगार को बचाने के लिए संसद तक आयेंगे।